मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को हरियाणा के असंध व तोशाम में भाजपा प्रत्याशियों समर्थन के में चुनावी सभायें कीं।

'सीमा पर गोली का जवाब गोले से दिया जाता है'

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा के असंध व तोशाम में चुनावी सभायें कीं

- **''विदेश में देश का अपमान शहजादे की फितरत है'' भजनलाल ने चुनाव सभा में राहुल गांधी पर कटाक्ष किया।**
- **उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से डबल इंजन सरकार के कारण हरियाणा में विकास की रफ्तार दुगुनी हो गई है।**

असंध (हरियाणा), 27 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को हरियाणा के असंध विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी योगेन्द्र राणा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का गरीब तथा मजदूर से कोई नाता नहीं है। इस पार्टी ने गरीब का हमेशा ही शोषण किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केवल 4 जातियों, किसान, मजदूर, युवा और महिला को केन्द्र में रखकर उनके उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी दुनिया में देश को शर्मसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वे सिक्ख भाइयों के लिए अनुचित टिप्पणी कर देश का मान गिराने का काम करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस सरकार के समय में 1984 के दौरान सिक्खों के साथ क्या हुआ था। वे जब भी विदेश जाते हैं तो देशद्रोहियों के साथ मुलाकात करते हैं, उनके साथ खिचड़ी पकाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सरकार ने हरियाणा के विकास को गति दी है। आज हरियाणा विकास के पथ पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, हाईवे का निर्माण और किसानों का कल्याण हमारी भाजपा सरकार ने किया है। इस विकास की गति को बनाए रखने के लिए भारी समर्थन के साथ भाजपा की सरकार बनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सीमा पर जब भी एक गोली आती है तो इधर से गोला ही जाता है। मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण और भारत के बढ़ते गौरव से पूरा विश्व परिचित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्रों को देखना चाहिए, किस प्रकार उसने जनता से झूठे वायदे किए। लेकिन हमारी सरकार जो कहती है, वो करती है।

जनसभा में शर्मा ने असंध विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी योगेन्द्र राणा को अधिकाधिक मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा में हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित हुए।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा के तोशाम विधानसभा क्षेत्र के बापोड़ा में भाजपा प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा जवानों और किसानों की धरती है। मेहनतकश किसान देश को आगे बढ़ाता है और किसान का बेटा मां भारती की सेवा में समर्पित रहता है। लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में नौकरियों और जमीनों में सिर्फ घोटाले किए और 2014 से पहले हरियाणा में नौकरी के लिए पैसे लगते थे। अब 2014 के बाद से डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान मिल रहा है और हरियाणा में विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई है।

मुख्यमंत्री ने आव्हान किया कि मजबूत राष्ट्र और विकसित हरियाणा के निर्माण के लिए हरियाणा में भाजपा की जीत की हैट्ट्रिक के साथ तोशाम प्रत्याशी श्रुति चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरियाणा प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह करनाल में मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने सहजता के साथ आमजन से मुलाकात की और फीडबैक लिया।

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी

बेगूसराय, 27 सितंबर। बेगूसराय से भाजपा के सांसद और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि रहे अमरेन्द्र कुमार अमर के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल करके यह धमकी दी गई। अमरेन्द्र कुमार अमर ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल किया गया और गिरिराज सिंह और उन्हें गाली गलौज की गई और अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस मामले में नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है।

बेगूसराय हेड क्वार्टर डी.एस.पी. ने बताया कि अधिवक्ता और सांसद प्रतिनिधि अमरेन्द्र अमर के द्वारा नगर

- **गिरिराज सिंह के सांसद प्रतिनिधि रहे अमरेन्द्र कुमार को वॉट्सएप पर कॉल के द्वारा धमकी दी गई।**

थाने की पुलिस को व्हाट्सएप पर एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान से एक व्हाट्सएप कॉल उनके फोन पर आया। इस कॉल में बेगूसराय सांसद एवं भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह और उनके सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र अमर को अंजाम भुगतने, यानी जान से मारने की धमकी दी गई।

अमरेन्द्र अमर ने पुलिस को इस बात की व्हाट्सएप पर आवेदन के जरिए सूचना दी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नंबर और लोकेशन को भी ट्रेस कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर धमकी देनेवाला शख्स कौन था और उसका मकसद क्या था।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों की दुबारा जिम्मेदारी तय की

- **आई.ए.एस., आई.एफ.एस. तथा आर.ए.एस. के नौ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से विभिन्न विभागों की मॉनिटरिंग, प्रगति व फीड बैक का काम देखेंगे।**

जयपुर, 27 सितम्बर। आई.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में लगे अधिकारियों की शुक्रवार को जिम्मेदारी दोबारा से तय की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में लगे कुल 9 आई.ए.एस., आई.एफ.एस. और आर.ए.एस. अधिकारियों को अलग-अलग विभागों का जिम्मा दिया गया है। ये अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से सभी विभागों की मॉनिटरिंग, कार्य योजनाओं की प्रगति, फीडबैक सहित अन्य कार्यों के कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे।

1. संदेश नायक (एस.एस.), पीएचईडी (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट), जीडब्ल्यूडी (वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट), आईजीएनपी (इंदिरा गांधी नहर परियोजना), सीएडी (काडमिनिस्ट्रेशन), माइंस एंड पेट्रोलियम, स्टेट सर्विस डिलीवरी वार रूम, सीएमआईएस (चीफ मिनिस्टर'स इन्फॉर्मेशन सिस्टम), डीआईपीआर (डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन्स)।
2. टीजे कविता (प्रिंसिपल ओएसडी), फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, सिविल एविएशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स, पीडब्ल्यूडी (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट), कैबिनेट, सीएमआरएफ (चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड), टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, जीएडी (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन), मोटर गैरेज, एस्टेट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीएमओ, आरटीआई एक्ट।
3. अंजू राजपाल (जेएस), मेडिकल एंड हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, आयुर्वेद, फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ट्राइबल एरिया डवलपमेंट, वुमन एंड चाइल्ड डवलपमेंट।
4. जय प्रकाश नारायण (डी.एस.), रेवेन्यू, कॉलोनाइजेशन, सैनिक कल्याण, देवस्थान, हायर/टेक/संस्कृत एजुकेशन, एजुकेशन (प्राइमरी/सेकेंडरी), लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी, प्लानिंग एंड मैन पावर, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वीआईपी रेफरेंस, रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रिवेंस।
5. सिद्धार्थ सिहाग - ज्वाइंट सेक्रेटरी, उद्योग, एमएसएमई (लघु और मध्यम उद्यम), खादी और ग्रामोद्योग, बीआईपी (राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड), ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम), पीएसयूएस (राज्य स्वामित्व वाले उपक्रम), रीको (राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन), कानून और न्याय, वित्त और कर, उत्पाद शुल्क, लघु बचत, सामान्य प्रावधायी निधि।
6. जगवीर सिंह- ज्वाइंट सेक्रेटरी, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जल संरक्षण और मृदा संरक्षण, प्रशासनिक सुधार, मुद्रण और स्टेशनरी, श्रम, रोजगार और कौशल विकास, कारखाना और बॉयलर, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, कृषि, कृषि विपणन, उद्यानिकी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पशुपालन, गोपालन, डेयरी, मत्स्य पालन।
7. ओपी बुनकर - ज्वाइंट सेक्रेटरी, शहरी विकास, स्थानीय निकाय, सहकारिता, संसदीय मामले, विधानसभा, चुनाव, आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, विकलांगता, शांति और अहिंसा विभाग, अल्पसंख्यक मामले, वक्फ।
8. राजकुमार सिंह - ओएसडी, -लोक शिकायत निवारण (मुख्यमंत्री कार्यालय)।
9. मनोज कुमार - डिप्टी सेक्रेटरी, लोक शिकायत निवारण (मुख्यमंत्री कार्यालय)।

''नाराज़'' सैलजा ने चुनाव प्रचार शुरु किया

- **गत एक पखवाड़े चुनाव अभियान से दूर रहीं कुमारी सैलजा गुरुवार को राहुल गांधी की कारनाल जिले की रैली में शामिल हुईं।**
- **वे टिकट वितरण में हुड्डा गुट को तरजीह दिये जाने के कारण नाराज़ थीं।**

चंडीगढ़ , 27 सितंबर। कांग्रेस से 'नाराज' बताई जा रहीं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज़ोर-शोर से पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में लग गयी हैं। लगभग एक पखवाड़े से प्रचार से दूर रहीं कुमारी सैलजा गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की करनाल जिले में रैली में शामिल हुई थीं।

रैली में हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी थे। खबरें थीं कि चुनावों में टिकट वितरण में हुड्डा गुट को तरजीह देने और फिर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की कुमारी सैलजा को लेकर कथित जाति सूचक टिप्पणी के बाद वह नाराज हो गयीं थीं और खुद को पार्टी प्रचार से दूर कर लिया था। उससे पूर्व उन्होंने इस आशय का भी बयान दिया था कि वह विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थीं और मुख्यमंत्री पद की भी दावेदार थीं। सूत्रों के अनुसार इस बीच, कांग्रेस उन्हें मनाने की कोशिश करती रही, हुड्डा ने भी कार्यकर्ता की विवादास्पद टिप्पणी के बाद तुरंत बयान दिया था कि कुमारी सैलजा उनकी बहन की तरह हैं और उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करने वाले के लिये कांग्रेस में जगह नहीं हो सकती।

भाजपा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

1995 में गुजरात में भाजपा की सरकार बनी थी। जब जोशी गुजरात भाजपा के संगठन महामंत्री बनाए गए थे तब मोदी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। मोदी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे पर उन्हें वर्ष 2001 तक इंतजार करना पड़ा और 2001 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब उन्हें पहला काम किया जोशी को गुजरात से बाहर करने का। जोशी को भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। तब से ही दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं।

अटकलें है कि अगर जोशी अध्यक्ष बन गए तो मोदी के कई कट्टर समर्थकों को हटा दिया जाएगा। मोदी खेमे में इस बात को लेकर भारी चिंता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री के रुप में मोदी के हटने की शुरुआत हो सकती है।

लोकायुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की

- **एफ.आई.आर. में मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी तथा साले को भी आरोपी बताया है।**
- **दूसरी ओर सिद्धारमैया ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है और उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष उनसे डरता है।**

बेंगलूरु, 27 सितंबर। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एम.यू.डी.ए.) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की है। सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस ने एम.यू.डी.ए. मामले में सिद्धरमैया और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए जन प्रतिनिधि कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज करने के निर्देश दिए थे।

कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक लोकयुक्त से इस मामले की जांच कर तीन महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज मैसूरु लोकयुक्त पुलिस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया।

इस मामले में सी.एम. को आरोपी नम्बर एक बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी पार्वती को आरोपी नम्बर दो बनाया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री के साले मल्लिकार्जुन स्वामी को आरोपी नम्बर 3 और देवराज को आरोपी नम्बर 4 बनाया गया है। मुख्यमंत्री पर अपने अधिकारों को दुरुपयोग करके, उनकी पत्नी के नाम मैसुरु में एम.यू.डी.ए. साइट आवंटित करने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता ने आज सेशंस कोर्ट में एक और रिट पिटिशन फाइल कर इस मामले की सी.बी.आई. से जांच करने की अपील की है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को दावा किया कि मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (एम.यू.डी.ए.) भूमि आवंटन मामले में उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष उनसे डरता है। इसके साथ ही, सिद्धरमैया ने कहा कि यह उनके खिलाफ पहला राजनीतिक मामला है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि मामले में अदालत द्वारा उनके खिलाफ जांच का आदेश दिये जाने के बाद भी वह इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कानूनी रूप से लड़ाई लड़ेंगे।

केंद्र सरकार पर सी.बी.आई., ई.डी. जैसी केंद्रीय एजेंसियों और देश भर के विपक्ष शासित राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन में राज्यपाल के 'हस्तक्षेप' के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की जरूरत है।

'कांग्रेस एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सजा से बचने के लिए काम करती है। भ्रष्टाचार के प्रति उनका यह रूख कर्नाटक में अभी दिखा है पर पूरे देश में यह पहले से है। पूनावाला ने कहा, कांग्रेस का मुख्य कार्य पहला भ्रष्टाचार करना है और कोर्ट ऑर्डर के बाद खुद को पीड़ित दर्शाना है। वे किसी भी सूरत में जाँच एजेंसियों के राज्य में आने से रोकेंगे। क्योंकि उन्हें लगता है कि लूटना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। कांग्रेस चोरों की पार्टी है और प्रोफेशनल अपराधियों की तरह बच निकलने की कोशिश में है और उन्होंने सी.बी.आई. को पहले से प्राप्त मंजूरी वापस ले ली है ताकि उनके खिलाफ जाँच ना हो सके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर तीन प्रहार हुए पहला तो यह राज्यपाल के मूडा जमीन मामले को बड़ा घोटाला मान कर जाँच के लिए सहमति दी, दूसरा प्रहार हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से जिसने राज्यपाल के जाँच के आदेश को सही माना। तीसरा प्रहार हुआ स्पेशल कोर्ट की तरफ से जिसने मुख्यमंत्री के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की अनुमति दे दी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी नेता माननीय राज्यपाल के फैसले पर सवाल किया जो अनुसूचित जाति के है। एक कांग्रेस नेता ने तो राज्यपाल को धमकी दे डाली और उन्हें अपशब्द भी कहे।

ई.डी. की चार्जशीट में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता माना

''ऐसी योजना बनाई कि अपराध से अर्जित जमीन का कन्ट्रोल उनके परिवार के पास हो''

- **ई.डी. ने दावा किया कि साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि जमीन उनसे या उनके परिवार से लिंक ना हो पाये।**

नई दिल्ली, 27 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लैंड फॉर जॉब मामले में दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लोगों से रिश्वत के तौर पर ज़मीन ली। चार्जशीट में आरोप है कि अपराध से अर्जित ज़मीन पर लालू प्रसाद यादव के परिवार का क़ब्ज़ा है। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने घोटाले की साज़िश इस तरह रची कि अपराध से अर्जित ज़मीन पर कंट्रोल तो उनके परिवार का हो लेकिन ज़मीन सीधे इनसे और परिवार से लिंक ना हो पाए।

चार्जशीट के मुताबिक, प्रोसीड ऑफ़ क्राइम, यानी अपराध से अर्जित आय को खपाने के लिए कई शैल कंपनियां खोली गईं और उनके नाम पर जमीनें लिखवाई गईं। तफ्तीश के दौरान खुलासा हुआ कि रेलवे की नौकरी और उसके नाम पर रिश्वत के तौर पर ज़मीन लेना दोनों लालू प्रसाद यादव ख़ुद तय कर रहे थे, इसमें उनका साथ दे रहा था उनका परिवार और करीबी अमित कत्याल। बतौर रिश्वत लिए गए कई ज़मीन के टुकड़े ऐसे थे जो कि लालू प्रसाद यादव के परिवार की ज़मीन के ठीक बराबर में स्थित थे। इन जमीनों को कौड़ियों के दाम पर खरीदा गया।

लालू प्रसाद यादव से जब उनकी बेटी को करोड़ों रुपए की जमीन गिफ्ट के तौर पर मिलने को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। चार्जशीट के मुताबिक राबड़ी देवी के कार्यकर्ताओं द्वारा जमीन के टुकड़े खरीदे और बाद में उसे लालू प्रसाद यादव की बेटी को उपहार में दिए। लालू प्रसाद यादव के निजी कर्मचारी गिफ्ट डीड में गवाह के रूप में मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के लिए पीओसी यानी अपराध से अर्जित आय (ज़मीन) हासिल करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश साबित करता है।

चार्जशीट के मुताबिक इस लेनदेन को दूर के रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट के रूप में पेश किया गया था, हालांकि दावे के विपरीत, मीसा भारती ने 25.03.2023 को अपने बयान के दौरान तथाकथित रिश्तेदारों हृदयानंद चौधरी और लल्लन चौधरी को जानने से इनकार कर दिया। साजिश के मुताबिक उक्त कंपनी ए के इंफोसिस्टम में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के बाद, अमित कत्याल ने 13-06-2014 को क्रमशः राबड़ी देवी (85प्रतिशत) और तेजस्वी प्रसाद यादव (15 प्रतिशत), जो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पुत्र हैं, को 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग हस्तांतरित कर दी, जिससे वो दोनों मेसर्स ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद भूमि के मालिक बन गए। इस तरह, कंपनी मेसर्स ए.के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी संपत्ति 1.89 करोड़ रुपये (कंपनी की बैलेंस शीट के अनुसार) है, को ''अपराध की आय'' के अंतिम लाभार्थियों यानी लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों ने 1 लाख रुपये की मामूली कीमत देकर अपने कब्जे में ले लिया।

क्या नायडू ने तिरुपति लड्डू की अशुद्धि का विवाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के घी का प्रयोग तिरुपति प्रसादम बनाने के लिए नहीं किया गया। यदि यह बात है तो, पूर्व मुख्यमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी को दोषी व जिम्मेवार कैसे ठहराया जा सकता है। आज कई स्वतंत्र विचार वाले लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं।

यदि ये आरोप हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल में दूषित घी प्रयुक्त किया जा रहा था तो उस समय कोई शिकायतें क्यों नहीं थीं तथा घी के सैम्पलों को टैस्ट नहीं किया जा रहा था। तो, क्या इस समय ऐसे आरोपों को साबित किया जा सकता है?

वास्तव में तो इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर इस स्तर पर पहुँचा दिया गया है कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन, सच्चाई यह है कि इस न्यूज़ को जो इतनी भारी पब्लिसिटी मिलने के बावजूद भी भक्त गणों की भीड़ तथा लड्डूओं की मांग बहुत ऊंची बनी हुई है, जो इस बात का संकेत है कि बहुत से लोगों ने इस विवाद को नज़र अंदाज़ कर दिया है।

लेकिन, राजनीतिक स्तर पर यह मुद्दा देश भर में गूंज रहा है। भाजपा नेता कड़ा रूख अपना रहे हैं तथा ''हिन्दू एकजुटता'' को पुनर्जीवित करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि लोकसभा आम चुनावों में पहले ढीला पड़ गया था। हिन्दू भावनाओं को एकजुट तथा प्रेरित करने के लिए यह मुद्दा बहुत काम आएगा।

क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राजनैतिक शत्रु को वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी को मात देने के लिए अनजाने में धार्मिक कार्ड खेला है और ऐसा मुद्दा उठाया है जिसमें उनके ईसाई मूल पर संदेह खड़ा किया गया है? और जो इकोसिस्टम मुख्यमंत्री को घेरे रहता है, उन्हें रेड्डी पर आरोप लगाने के लिए उकसा रहा है। रेड्डी ने पक्षपात किया तथा हिन्दू मंदिर के प्रबंधन में ईसाईयों की नियुक्ति की।

यह मुद्दा जनगमोहन रेड्डी की बालाजी मंदिर की प्रस्तावित यात्रा से उस समय और भी प्रचंड एवं गरम होने वाला था, जब नायडू, पवन कल्याण तथा अन्य भाजपा नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी मंदिर जाते हैं तो वे तिरुमला के बालाजी मंदिर के अधिष्ठाता देव वैंकटेश्वर स्वामी के प्रति अपनी आस्था की घोषणा करें। अब, इस आवेशपूर्ण माहौल में, रेड्डी ने मंदिर की अपनी प्रस्तावित यात्रा निरस्त कर दी। उनके निन्दकों का कहना है कि रेड्डी ने अपनी प्रस्तावित यात्रा इसलिये रद्द की है क्योंकि वे अपनी आस्था के बारे में इस प्रकार की घोषणा करना नहीं चाहते थे। सूत्रों का कहना है कि जब जगनमोहन रेड्डी के पिता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब वे कई बार मंदिर गये तथा उन्होंने इस घोषणा पर हस्ताक्षर भी किये थे, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य अनेक लोगों ने किये हैं।

चूँकि इस मंदिर में दर्शन करने के संबंध में यह नियम लागू है, इसलिये सबको इसका पालन करना ही होता है।

अब आंध्र प्रदेश सरकार ने नौ सदस्यों की एक ''स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम'' गठित कर दी है, जो इस प्रकरण की व्यापक जाँच करेगी। लेकिन राजनैतिक विश्लेषक यह जानना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे की जाँच-पड़ताल कराये बिना, क्या नायडू का इतना हल्ला-गुल्ला सही था?

अब इस गहन जाँच के बाद ही यह तथ्य सामने आयेगा कि क्या लड्डू दूषित घी से बनाये जाते थे। इस बिन्दु पर अनिश्चितता एवं संदेह की स्थिति है। क्या यह मंदिर -स्तर पर प्रशासकीय असफलता है या फिर मंदिर को अपवित्र या बदनाम करने की कोई अनर्थकारी एवं सुनियोजित गतिविधि है, जैसा कि कुछ दक्षिणपंथी ऐक्टिविस्ट दावा कर रहे हैं।

और अगर बाद में सच्चाई या ऐसी कोई चीज सामने आती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी के खिलाफ लगाये जा रहे सारे आरोपों के विपरीत हो, तो उस स्थिति में क्या होगा?

यही कारण है कि चेन्नई के सुमन्त सी. रमण जैसे विश्लेषक, जो इस मुद्दे को बारीकी से देख-परख रहे हैं, यह चाहेंगे कि नायडू तथा उनके सहायक किसी पर उँगली उठाने से पहले, जाँच पूरी हो जाने तक प्रतीक्षा करें।

पंजाब भाजपा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निन्दकों का कहना है कि पार्टी का वोट शेयर तो इसलिये बढ़ा, क्योंकि 2024 में पार्टी राज्य की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि 2019 में, पार्टी शिरोमणि अकाली दल के मित्रदल के रुप में केवल 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी के कुछ ग्रुप खासतौर से लुधियाना और फिरोज़पुर सीटों पर भाजपा की हार का दोषारोपण जाखड़ पर कर रहे हैं।

पहले तो कांग्रेस में, और अब भाजपा में जाखड़ की उपेक्षा को इस तथ्य से जोड़कर देखा जा रहा है कि वे पगड़ीधारी नेता नहीं हैं। कांग्रेस ने जाखड़ की उम्मीदवारी की उपेक्षा करते हुये, मुख्यमंत्री पद के लिये चरणजीत सिंह चन्नी को आगे बढ़ाया था। और एक सिक्ख उम्मीदवार के लिये उसी प्रकार की प्राथमिकता भाजपा ने दिखाते हुये, रवनीत सिंह बिट्टू को नरेन्द्र मोदी की मंत्रिपरिषद में मंत्री बना दिया था, जबकि बिट्टू लोकसभा चुनाव हार गये थे।

सुनील जाखड़ स्व. बलराम जाखड़ के पुत्र हैं। बलराम जाखड़ पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे तथा दो कार्यकालों में, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। इसके अलावा, किसानों में भी उनका मान-सम्मान था क्योंकि उन्होंने 1965 में ''भारतीय कृषक समाज'' नामक संगठन की स्थापना भी की थीं। कांग्रेस में रहते हुये, सुनील अबोहर सीट से तीन बार विधायक तथा एक बार गुरदासपुर लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुये थे। जहाँ भाजपा में उनकी स्थिति कामचलाऊ बनी हुई है, वहीं कांग्रेस में उनकी वापसी की संभावना भी खारिज की जा रही है।

एकल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बजाय भाजपा नेता और मंत्री अहंकार और अनादर का सहारा लेते हैं। समाधान सीधा है, एक एकल, सरलीकृत जीएसटी और ये कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी कितना जटिल है इसका नमूना देखिए कि क्रीम बन पर 18 प्रतिशत जीएसटी है जबकि क्रीम पर पांच प्रतिशत और बन पर पांच प्रतिशत जीएसटी है।

'सी.बी.आई...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उठाये गये थे। इस आशय की एक घोषणा की माँग की गई थी कि उन वॉलंटरी शिक्षकों के नियमितीकरण के निर्देश देने वाले आदेश शून्य एवं अकृत (नल एंड वॉइड) किये जाते हैं तथा ऐसे किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं, जिसके पक्ष में ये आदेश दिये गये थे।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, **जयपुर कार्यालयः** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, **उदयपुर कार्यालयः** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालयः**-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908